भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 329
दिनांक 12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान

*329. श्रीमती कमलेश जांगड़े:
श्री प्रवीण पटेल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितना अनुदान संवितरित किया गया;

(ख) क्या सरकार ने लाभग्राही राज्यों में ऐसे अनुदानों के माध्यम से वित्तपोषित परियोजनाओं से सीधे लाभान्वित परिवारों अथवा व्यक्तियों की संख्या के संबंध में आंकड़े एकत्र किए हैं;

(ग) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) छत्तीसगढ़ सहित सभी लाभग्राही राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा आयोग के ऐसे अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) राजस्थान में सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग (XV-एफसी) के अनुदानों से वित्तपोषित परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान" के सम्बंध में दिनांक 12.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लेखित विवरण।

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान का राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख) जी नहीं, महोदय।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) छत्तीसगढ़ सहित राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकारों को राज्य, ज़िला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी के लिए एक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। अप्रैल 2020 में, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज वेब पोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) की शुरूआत की, जो पंचायतों के सभी वित्तीय कार्यों - योजना से लेकर भुगतान तक को एकीकृत करता है। इस प्रणाली से प्राप्त प्रगति के आंकड़े (प्रोग्रेस डेटा) को निगरानी के लिए पोर्टल पर दर्शाया जाता है।

राज्य, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों के उपयोग की व्यवस्थित निगरानी के लिए ई-ग्राम स्वराज एप्लिकेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके योजना मॉड्यूल के माध्यम से, राज्य यह ट्रैक करते हैं कि पंचायती राज संस्थाएँ अपनी विकास योजनाओं में स्थानीय आवश्यकताओं को कैसे शामिल करती हैं, जिससे बजटीय प्रावधानों के साथ समन्वय सुनिश्चित होता है। प्रगति रिपोर्टिंग मॉड्यूल, अनुदान-वित्त पोषित गतिविधियों से संबंधित भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है, जबकि लेखा मॉड्यूल, वित्तीय लेनदेन और व्यय पैटर्न की विस्तृत ट्रैकिंग सुनिश्चित करता है। ये सभी सुविधाएँ मिलकर राज्यों को अनुदान उपयोग की व्यापक समझ प्रदान करती हैं, जिससे संसाधनों का अधिक प्रभावी और पारदर्शी आवंटन और प्रबंधन संभव होता है।

पारदर्शिता को और बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के लिए ई-ग्राम स्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया है, जिससे विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अतिरिक्त, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन ऑडिटिंग को सक्षम बनाने के लिए अप्रैल 2020 में ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया था। यह टूल केंद्रीय वित्त आयोग के धन के पारदर्शी उपयोग में सहायता करता है और पंचायत-स्तरीय वित्तीय निगरानी को मज़बूत करता है।

(ङ) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राजस्थान में 15वें वित्त आयोग अनुदान का जिलावार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

***

अनुबंध-I

(दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत वितरित/जारी अनुदानों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य	जारी अनुदान (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	2109.97
2	बिहार	4109.01
3	छत्तीसगढ़	1185.25
4	गुजरात	1271.50
5	हरियाणा	1012.51
6	हिमाचल प्रदेश	229.19
7	कर्नाटक	2133.25
8	केरल	1334.00
9	मध्य प्रदेश	1629.45
10	महाराष्ट्र	3169.72
11	ओड़िशा	1851.00
12	पंजाब	788.90
13	राजस्थान	2803.69
14	सिक्किम	32.34
15	तमिलनाडु	2270.74
16	त्रिपुरा	156.31
17	उत्तर प्रदेश	7994.00
18	उत्तराखण्ड	234.91
19	पश्चिम बंगाल	3472.22
कुल		**37787.96**

अनुबंध-II

(दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 329 के भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध)

राजस्थान में पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान से वित्त पोषित परियोजनाओं का जिलावार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	जिले का नाम	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अजमेर	106.71	78.86	81.66	77.25	87.61
2	अलवर	169.66	125.38	129.83	122.83	127.16
3	बांसवाड़ा	139.19	102.86	106.51	100.77	96.21
4	बारां	84.81	62.67	64.90	61.40	58.17
5	बाड़मेर	188.58	139.36	144.31	136.53	153.55
6	भरतपुर	118.22	87.36	90.46	85.58	79.47
7	भीलवाड़ा	136.64	100.97	104.56	98.92	101.58
8	बीकानेर	151.16	111.71	115.67	109.43	123.14
9	बूंदी	83.54	61.73	63.92	60.48	66.28
10	चित्तौड़गढ़	97.25	71.86	74.42	70.40	72.16
11	चुरू	108.33	80.05	82.90	78.43	88.58
12	दौसा	103.46	76.46	79.17	74.90	65.54
13	धौलपुर	75.15	55.54	57.51	54.41	43.41
14	डूंगरपुर	110.96	82.00	84.91	80.33	74.28
15	गंगानगर	120.80	89.27	92.44	87.46	83.24
16	हनुमानगढ़	102.61	75.83	78.52	74.29	76.33
17	जयपुर	183.79	135.82	140.64	133.06	153.27
18	जैसलमेर	122.85	90.79	94.01	88.94	104.52
19	जालौर	117.13	86.56	89.64	84.80	86.87
20	झालावाड़	91.10	67.33	69.72	65.96	61.63
21	झुंझुनूं	99.14	73.26	75.86	71.77	67.57
22	जोधपुर	170.08	125.69	130.15	123.13	141.76
23	करौली	101.34	74.89	77.55	73.37	63.65
24	कोटा	66.93	49.46	51.22	48.45	46.32
25	नागौर	172.25	127.29	131.81	124.70	131.51
26	पाली	123.20	91.04	94.28	89.19	94.30
27	प्रतापगढ़	80.91	59.79	61.91	58.57	49.63
28	राजसमंद	74.19	54.83	56.77	53.71	52.52
29	सवाई माधोपुर	87.59	64.73	67.03	63.41	53.26
30	सीकर	117.60	86.90	89.99	85.14	86.64
31	सिरोही	78.17	57.76	59.82	56.59	52.37
32	टोंक	91.10	67.33	69.72	65.96	70.65
33	उदयपुर	187.58	138.62	143.54	135.80	142.53
	कुल	3862.00	2854.00	2955.34	2795.94	2855.71

***